



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

No. 194]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 2004/भाद्र 8, 1926

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 2004/BHADRA 8, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2004

जांच शुरुआत

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : ई यू, जार्जिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/12/2004-डीजीएडी.— यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियम कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 23 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 65/1/2001-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, जॉर्जिया और सिंगापुर (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था।

और यतः दिनांक 7 मार्च, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 40/2003-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. समीक्षा के लिए अनुरोध

और यतः उपरोक्त नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी प्राप्त निश्चयात्मक सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं। उपरोक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गयी समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली निश्चयात्मक सूचना के आधार पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक उचित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटन के प्रतिसंतुलन के लिए शुल्क को लगातार जारी रखना आवश्यक है, कि शुल्क की समाप्ति अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाएं तो क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यूरोपीय संघ के एक निर्यातक अर्थात् मै0 बी ए एस एफ लिमिटेड, जर्मनी ने लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए यूरोपीय आयोग के जरिए अनुरोध किया है।

3. समीक्षा के लिए आधार

आवेदक ने दावा किया है कि पाटन और क्षति दोनों की परिस्थितियाँ काफी परिवर्तित हो गई हैं जिनके कारण लागू पाटनरोधी उपायों की समीक्षा करना आवश्यक है। निर्यातक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया है कि भारत को उनकी निर्यात कीमत उनकी उत्पादन की लागत से और घरेलू बाजार में उनकी बिक्री कीमत से काफी अधिक है और इसलिए भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन नहीं हुआ है। यह भी दावा किया गया है कि यूरोपीय संघ से निर्यातित वस्तुओं की पहुँच कीमत भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है और इससे कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है। आवेदक का यह भी दावा है कि डी पी सी ओ कीमत अर्थात् भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की अधिकतम बिक्री कीमत, जैसा कि डी पी सी ओ द्वारा निर्धारित किया गया है, को 2003 से संशोधित करके कम कर दिया गया है और यूरोपीय संघ से आयातों का पहुँच मूल्य भी डी पी सी ओ कीमतों से अधिक है जिससे नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री की सूचना मिलती है। अतः आवेदक का दावा है कि यूरोपीय संघ से कोई पाटन नहीं हो रहा है और घरेलू उद्योग को यूरोपीय संघ से होने वाले आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

4. जांच शुरूआत

परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई निश्चयात्मक सूचना के मदेनजर लागू उपाय की समीक्षा करना जरूरी हो जाने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के प्रावधान के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मदेनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझते हैं।

दिनांक 23 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं० 65/1/2001-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेकर प्राधिकारी एतद्वारा नियमों के अनुसार जांच आरम्भ करते हैं ताकि यह समीक्षा की जा सके कि क्या यूरोपीय संघ, जॉर्जिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन ए पामिटेड के आयातों पर शुल्क को लगातार लगाया जाना पाटन के प्रति संतुलन के लिए जरूरी है, शुल्क को समाप्त अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाने से क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद विटामिन ए पामिटेड है जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आई टी सी एच एस वर्गीकरण की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में शीर्ष सं० 293621.00 के अंतर्गत आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

प्रक्रिया

जांच द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन की समाप्ति के लिए शुल्क को जारी रखा जाना आवश्यक है तथा क्या शुल्क को हटाए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) समीक्षा में दिनांक 23 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं० 65/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

(ii) इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की है। तथापि क्षति विश्लेषण की अवधि, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 तक की होगी।

(iii) इस जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, जॉर्जिया तथा सिंगापुर हैं।

(iv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

6.1 सूचना देना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में

संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में एवं तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करें एवं अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने निवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन करने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसे जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा।

6.2 समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु किसी प्रकार के अनुरोध लिखित में भेजे जाने चाहिए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

6.3 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th August, 2004
INITIATION
(MID-TERM REVIEW)

Subject : Initiation of Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports of Vitamin A Palmitate originating in or exported from the EU, Georgia and Singapore.

No. 15/12/2004-DGAD—WHEREAS having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), vide Notification Number 65/1/2001-DGAD dated 23rd January 2003, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Vitamin A Palmitate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the European Union, Georgia and Singapore (hereinafter referred to as subject countries).

AND WHEREAS definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 40/2003-Customs dated 7th March 2003.

2. Request for Review

WHEREAS the Rules require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive antidumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

In terms of the above provision one of the exporters from the European Union i.e. M/s BASF Limited, Germany has filed a request, through the European Commission, for a changed circumstances mid-term review of the antidumping duty in force,

3. Grounds for Review

The applicant claims that the conditions of both, dumping and injury have changed substantially requiring a review of the antidumping measure in force. The exporter has *inter alia* claimed that their export price to India is much above their cost of production, as well as their selling price in the domestic market and therefore, there is no dumping of the subject goods in the Indian market. It has also been claimed that the landed price of the goods exported from the European Union is above the selling price of the domestic industry in India and there is no price undercutting. The applicant also claims that the DPCO price i.e., the maximum selling price of the for the subject goods in the Indian market as determined by DPCO has been revised downwards since 2003 and the landed value of the imports from the European Union is above the DPCO prices, indicating negative price underselling. Therefore, the applicant claims that no dumping is taking place from the European Union and the domestic industry is not suffering any injury on account of the imports from the European Union.

4. Initiation

Having regards to the positive information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the Anti Dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra.

Having decided to review the final findings notified vide Notification No.65/1/2001-DGAD dated 23rd January 2003, the Authority hereby initiates the investigations in terms of the Rules, to review whether continued imposition of the duty on imports of Vitamin A Palmitate originating in or exported from the European Union, Georgia and Singapore, is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

5. Product under Consideration

The product involved in the original investigation and the current review is Vitamin A Palmitate falling under heading No. 293621.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

6. Procedure

The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No.65/1/2001-DGAD dated 23rd January 2003
- (ii) The period of investigation for the purpose of this review will be 1st April 2003 to 31st March 2004. However, injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003-04.
- (iii) The countries involved in this investigation are the European Union, Georgia and Singapore.
- (iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

6.1 Submission of Information:

The exporters in subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.
Fax: 91-11-23014418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making confidential submissions before the Authority is required to file a non-confidential version of the same, for placing the same in the public folder for inspection by all other interested parties to the investigation.

6.2 Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

6.3 Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the submissions made by other interested parties before the Authority. In case an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority